

Stop It Or We Will: Supreme Court To Team Yogi About Fining CAA Protests

New Delhi: The Uttar Pradesh government was told off by the Supreme Court for trying to recover money for property damage during the 2019 anti-Citizenship (Amendment) Act protests from those identified as protesters. The court said it is giving one final opportunity to the state to withdraw the proceedings or it will quash it for being in violation of the law. "You have to follow the due process under the law. Please examine this, we are giving one opportunity till February 18," the court said. The Uttar Pradesh government has acted like a "complainant, adjudicator and prosecutor" in conducting the proceedings to attach the properties of the accused, said a bench of justices DY Chandrachud and

Surya Kant.

"Withdraw the proceedings or we will quash it for being in violation of the law laid down by this court," the bench said. The top court was hearing a plea filed by Parwaz



Arif Titu seeking quashing of notices sent to alleged protesters by the district administration for recovering losses caused by damage to public properties during the anti-Citizenship (Amendment)

Act (CAA) agitations in Uttar Pradesh and asked the state to respond to it. The plea said the notices have been sent in an "arbitrary manner" and cited instances where a notice has been sent to a man who had died six years ago at the age of 94 and also to several others including two people who are aged above 90. The counsel for the state government, Garima Prashad, said that 106 FIRs were registered against 833 rioters and 274 recovery notices were issued against them. Out of the 274 notices, recovery orders were passed in 236 while 38 cases were closed, said the UP government's counsel. The bench said, "The Supreme Court has passed two judgements in 2009 and 2018, which said that judicial

officers should be appointed in claim tribunals but instead you appointed Additional District Magistrates (ADM)".

Justice Surya Kant said, "Madam Prashad, this is just a suggestion. This plea concerns only a set of notices sent in December 2019, in relation to one kind of agitation or protest. You can withdraw them with a stroke of a pen. 236 notices in a big state like UP is not a big thing. If you are not going to listen, then be ready to face the consequences. We will tell you how the Supreme Court judgements need to be followed". Justice Chandrachud asked why ADMs were conducting the proceedings when the court had directed that adjudication has to be done by a judicial officer.

BMM professor duped of Rs 3.9 lakh by cyber fraudster in Mumbai

The south region cyber cell has registered an FIR against unknown persons for duping a Bachelor Of Mass Media (BMM) professor of over Rs 3.9 lakh. The accused posed as an customer care executive of a cellphone service provider and asked the complainant to renew his KYC. The complainant lost money in multiple transactions after he shared an OTP with fraudsters.

Professor Shridhar Naik, who has been a leading faculty for BMM students across Mumbai, approached the south Mumbai cyber cell on Monday after being duped of Rs 3,99,500 by a cyber fraudster. "The Mumbai police immediately registered an FIR in the matter and started the probe," Naik told mid-day.

According to Naik, on Friday he received an SMS from Airtel asking him to renew his KYC. "I

called the given number. The executive who identified himself as Rahul asked me to make a payment to an HDFC Bank account. Later, I was asked to fill in an OTP," Naik said in his complaint to cyber police.

According to Naik, the caller filled out his KYC form after taking the details from him, which included his PAN number and bank account details. "He sent me a link of a nationalised bank and asked me to make payment of Rs 10, which I did," Naik told mid-day. The caller then informed Naik that his KYC was renewed. However, after some time, three transactions of Rs 20,000, Rs 1 lakh and Rs 99,500 took place from Naik's account. He informed the bank to get his accounts blocked. "On the night of February 5, I got a call from the same number again. The caller, who identified himself as Amit Mishra, asked me to send the OTP. When I confronted him about the previous transactions, he said he could resend the amount to me after being provided with the OTP," Naik said in his statement to police. "On the evening of February 6, I found my mobile and internet banking unblocked and the mini statement showed that Rs 50,000 were transferred out of my account in two installments. When I called the bank, I was told that they would again block my mobile banking app and UPI, which were unblocked." The south region cyber cell has registered an FIR and is investigating the matter further. The cyber police have found that Naik's phone was cloned by the fraudsters after he clicked the link.

सेंट्रल रेलवे ने मुंबई की लोकल ट्रेनों के लिए मुफ्त इंफोटेनमेंट सेवा शुरू की



अपनी यात्रा के दौरान फिल्में, टीवी शो और शैक्षिक कार्यक्रम मुफ्त में देख सकते हैं क्योंकि मध्य रेलवे ने श्रुकवार को "कॉर्टेंट आन डिमांड" इंफोटेनमेंट

"कॉर्टेंट आन डिमांड" इंफोटेनमेंट सेवा प्रदान करने के लिए मैसर्स मार्गो नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के साथ हाथ मिलाया है। मध्य रेलवे (सीआर) ने महाप्रबंधक अनिल कुमार लाहोटी की उपस्थिति में १६५ उपनगरीय लोकल ट्रेनों में से १० में इस सेवा की शुरूआत की। इसमें कहा गया है कि यात्रियों को अपने उपकरणों पर शुगर बॉक्स एप डाउनलोड करना होगा, जिसके बाद मुफ्त इंफोटेनमेंट सामग्री तक पहुंचने से पहले उन्हें अपना मोबाइल नंबर दर्ज करने पर एक ओटीपी सेवा की शुरूआत की है। रेलवे ने एक बयान में इसकी जानकारी दी। बयान में कहा गया है कि मध्य रेलवे ने शुगरबॉक्स नेटवर्क मोबाइल एप के माध्यम से

लिए कॉर्टेंट आन डिमांड" को लोकल ट्रेनों में यात्रा करने वाले लोग अब

अगले महीने मुंबई पहुंचेगी मेट्रो-३ की पहली रेक, अप्रैल में शुरू हो सकता है ट्रायल रन

मुंबई: मुंबई की पहली भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर पर अप्रैल या मई में पहली बार मेट्रो दैड़ सकती है। कॉरिडोर पर ट्रायल रन शुरू करने के लिए आंश्विक्रेस के श्रीसिंही में मेट्रो की पहली रेक बनकर तैयार हो चुकी है। अगले डेढ़ माह में यह रेक मुंबई पहुंच जाएगी। मुंबई मेट्रो रेल को पॉर्शेन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) के एक अधिकारी के मुताबिक, रेक के मुंबई पहुंचने के बाद ट्रायल रन आरंभ करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कोलाबा-बांद्रा-सिंज के बीच ३.३ किमी लंबे मेट्रो ३ कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है।

कॉरिडोर के लिए आंश्विक्रेस की श्रीसिंही में सेक इन इंडिया के तहत ८ डिब्बों की रेक तैयार की जा रही है। एमएमआरसीएल अन्यान्युक्ति सुविधा के साथ यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के

लिए आंश्विक्रेस के बीच ट्रायल रन का निर्माण करवा रही है। यह ट्रेन ड्राइवर लैस होंगी। इसके अलावा कोच फुल ऐसी होंगे, साथ ही कोच के अंदर एलसीडी



स्क्रीन, डिजिटल मैप इंडीकेटर, अग्नि शमन वंत्र, स्मार्क डिटेक्टर, इमरजेंसी के लिए वायस कम्युनिकेशन और पीएम स्टिम भी होंगा। इसके अलावा शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति के लिए डेंडीकेटेड बींचेवर एसिया की भी व्यवस्था ट्रेन में की गई है। केंद्र और राज्य सरकार के

लिए कॉर्टेंट आन डिमांड" को लोकल ट्रेनों में सेवा में स्थायी,

लिए न ही सरकारी अधिकारी आ

रहे और न ही इन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। महाराष्ट्र स्टेट मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन मुंबई के

अध्यक्ष डॉ. सचिन मुलकुटकर ने बताया

के लिए न ही सरकारी अधिकारी आ

रहे और न ही इन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। महाराष्ट्र स्टेट मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन मुंबई के

अध्यक्ष डॉ. सचिन मुलकुटकर ने बताया

के लिए न ही सरकारी अधिकारी आ

रहे और न ही इन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। महाराष्ट्र स्टेट मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन मुंबई के

अध्यक्ष डॉ. सचिन मुलकुटकर ने बताया

के लिए न ही सरकारी अधिकारी आ

रहे और न ही इन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। महाराष्ट्र स्टेट मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन मुंबई के

अध्यक्ष डॉ. सचिन मुलकुटकर ने बताया

के लिए न ही सरकारी अधिकारी आ

रहे और न ही इन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। महाराष्ट्र स्टेट मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन मुंबई के

अध्यक्ष डॉ. सचिन मुलकुटकर ने बताया

के लिए न ही सरकारी अधिकारी आ

रहे और न ही इन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। महाराष्ट्र स्टेट मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन मुंबई के

अध्यक्ष डॉ. सचिन मुलकुटकर ने बताया

के लिए न ही सरकारी अधिकारी आ

रहे और न ही इन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। महाराष्ट्र स्टेट मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन मुंबई के

अध्यक्ष डॉ. सचिन मुलकुटकर ने बताया

के लिए न ही सरकारी अधिकारी आ

रहे और न ही इन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। महाराष्ट्र स्टेट मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन मुंबई के

अध्यक्ष डॉ. सचिन मुलकुटकर ने बताया

के लिए न ही सरकारी अधिकारी आ

रहे और न ही इन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। महाराष्ट्र स्टेट मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन मुंबई के

अध्यक्ष डॉ. सचिन मुलकुटकर ने बताया

के लिए न ही सरकारी अधिकारी आ

रहे और न ही इन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। महाराष्ट्र स्टेट मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन मुंबई के

अध्यक्ष डॉ. सचिन मुलकुटकर ने बताया

के लिए न ही सरकारी अधिकारी आ

रहे और न ही इन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। महाराष्ट्र स्टेट मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन मुंबई के

अध्यक्ष डॉ. सचिन मुलकुटकर ने बताया

के लिए न ही सरकारी अधिकारी आ

रहे और न ही इन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। महाराष्ट्र स्टेट मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन मुंबई के

अध्यक्ष डॉ. सचिन मुलकुटकर ने बताया

के लिए न ही सरकारी अधिकारी आ

रहे और न ही इन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। महाराष्ट्र स्टेट मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन मुंबई के

अध्यक्ष डॉ. सचिन मुलकुटकर ने बताया

के लिए न ही सरकारी अधिकारी आ

रहे और न ही इन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। महाराष्ट्र स्टेट मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन मुंबई के

अध्यक्ष डॉ. सचिन मुलकुटकर ने बताया

